ईएसआई में पैसे की कोई कमी नहीं, फ़िर भी स्टाफ़ और दवाओं की भारी कमी

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई के हरियाणा क्षेत्र में 120 करोड़ से अधिक रुपया फालतू पड़ा है तथा हर वर्ष श्रमिकों से प्राप्त होने वाले रुपये का आधा भी खर्च नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसे खर्च करने अथवा सेवाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा हरियाणा सरकार के श्रम विभाग का है जो कि पहले स्वास्थ्य विभाग का होता था।

देश भर की राज्य सरकारों की फ़िज़ूलखर्चियों तथा राजनीतिक उद्देश्यों से धन की बर्बादी को नियंत्रित रखने की दृष्टि से ईएसआई निगम ने राज्य सरकारों को पैसा देने के कुछ नियम बनाये हैं जिनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार फ़ेर-बदल किये जाते रहे हैं। ऐसे ही एक नियम के तहत ईएसआई निगम प्रत्येक बीमाकृत के लिए राज्य सरकार को गत वर्ष तक 1000 रुपये तथा अब 1200 रुपये खर्चने की अनुमति देती है यानी कि राज्य भर के साढ़े छः लाख बीमाकृतों के लिये 78 करोड़ रुपये का खर्च मानती है जिसका सात भाग ईएसआई निगम तथा एक भाग राज्य सरकार को खर्चना होता है। निगम ने इस रकम को भी दो भागों में बांटा है। 700 रुपये वेतन तथा तमाम तरह के प्रशासनिक कार्यों के लिये तथा 500 रुपये दवाइयों के लिये रखे हैं। यदि ईएसआई निगम ऐसा न करे तो ये सारी रकम वेतन व भत्तों आदि में ही निपटा दें तो कोई बड़ी बात नहीं।

इसके अलावा तमाम तरह के औज़ार, मशीनें, एंबुलेंस, इमारतों के बनाने व रख-रखाव का खर्च भी निगम स्वयं वहन करती है जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। इसके बावजूद भी सभी तरह के साजो-सामान का नितांत अभाव इन अस्पतालों में बना ही रहता है जैसे कि एक्स-रे मशीन का उदाहरण दिया गया है।

दवाइयों के खाते में राज्य सरकार वर्ष 2007-08 में राज्य भर के साढ़े पांच लाख बीमाकृतों के लिये 22 करोड़ रुपया ईएसआई निगम से प्राप्त कर सकती थी, जबकि राज्य सरकार ने मांगा ही कुल 16 करोड़। इसी तरह वर्ष 2008-09 में 26 करोड़ की जगह मांगा ही कुल 18 करोड़। मौजूदा 2009-10 के बजट में, जब बीमाकृतों की कुल संख्या 6.75 लाख हो गई है, सरकार ईएसआई निगम से दवाइयों के नाम पर 33.5 करोड़ प्राप्त कर सकती थी, लेकिन प्राप्त किया कुल 18.84 करोड़। यानी कि राज्य सरकार भारी मात्रा में दवाइयों का वह पैसा छोड़ रही है जो कि वह निगम से ले सकती थी, शायद केवल इसलिये कि सरकार अपने आठवें हिस्से के खर्च को बचा सके।

दूसरी ओर वेतन आदि के लिये रखे गये दूसरे भाग यानी कि 700 रुपये, वहां सरकार को भारी घाटा पड़ रहा है, क्योंकि वेतन लगातार बढ़ रहे हैं खास कर छठे वेतन आयोग के बाद से। जानकारों के मुताबिक नवंबर माह में वेतन देने के बाद सरकार का तमाम (वेतन) बजट समाप्त हो चुका है। लेकिन वेतन तो रोका नहीं जा सकता। इसलिये सरकार को अपने आठवें हिस्से से अधिक की रकम दूसरे खातों से निकाल कर वेतन की अदायगी करनी दिखाई पड़ रही है, जिससे राज्य सरकार के पसीने छूटे हुये हैं। लेकिन ईएसआई निगम ने इसका समाधान भी दिनांक 1.4.09 को ही कर दिया था, क्योंकि निगम के अधिकारी जानते थे कि यह समस्या आयेगी। परंतु राज्य सरकार के अधिकारियों व मंत्री को इस समाधान की ओर झांकने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। यह भी संभव है कि इससे संबंधित पत्र किसी उच्चाधिकारी ने पढ़ा ही न हो। दिनांक 1.4.09 को जारी परिपत्र में ईएसआई निगम ने कहा है कि वह बढ़े हुये तमाम वेतन में अपनी हिस्सेदारी अदा करने को तैयार है बशर्ते कि राज्य सरकार निगम के मानदंडों को ईमानदारी से लागू करे। ये मानदंड क्या हैं जिन्हें लागू करने से राज्य सरकार कतरा रही है?

पहला मानदंड तो यह है कि 2000 बीमाकृतों पर एक डॉक्टर होना चाहिए औषधालयों में, अस्पताल के डॉक्टर इससे अलग होंगे। प्रति एक लाख बीमाकृतों पर एक 100 बिसतरों वाला अस्पताल होना चाहिए। फ़रीदाबाद के एक लाख, साठ हज़ार बीमाकृतों के लिए एक अस्पताल एनआईटी के तीन नंबर में ओर दूसरा सेक्टर-8 में है। एनआईटी वाला अस्पताल कहने को तो 200 बिस्तरों का है, लेकिन ईएसआई मानदंडों के हिसाब से इसमें सुविधायें 100 बिस्तरों की भी नहीं है। इसी तरह सेक्टर-8 वाले अस्पताल की इमारत तो 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की है, लेकिन इसे दर्जा दिया है 50 बिस्तर का, पर ईएसआई मानकों के अनुसार 10 बिस्तरों की भी सुविधा नहीं है।

ईएसआई मानकों के अनुसार 100 बिस्तर अस्पताल में 60 डॉक्टर, 100 नर्स, 10 प्रयोगशाला तकनीशियन, 8 रेडियोग्राफ़र, 15 ऑपरेशन थियेटर स्टाफ़, 12 फार्मासिस्ट, 100 चपरासी तथा 37 सफ़ाईकर्मी होने चाहिये। कार्यालय क्लर्क आदि की संख्या 20 निर्धारित की गई है। इन सब मानकों के अनुसार नियुक्तियां करने पर जो भी खर्च आयेगा, जितना भी भत्ता बनेगा, उस सबका मात्र आठवां भाग राज्य सरकार को देना होगा जबकि शेष सात भाग ईएसआई निगम को देना होता है जिसके लिये वह सदैव तैयार है।

लेकिन राज्य सरकार ने तमाम मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए फ़रीदाबाद की डिस्पेंसरियों में 80 डॉक्टरों की जगह मात्र 43 पद स्वीकृत कर रखे हैं, उनमें से भी छः रिक्त पड़े हैं तो बाकी बचे 37 डॉक्टर 1,60000 बीमाकृतों को कैसे निपटाते हैं, समझना कठिन नहीं है। इन 37 डॉक्टरों में से दो पलवल तथा दो तिगांव की डिस्पेंसरियों में बैठते हैं। इन डिस्पेंसरियों का नेटवर्क अति कमज़ोर होने की वजह से अस्पताल पर असहनीय दबाव बढ़ता जाता है।

इसी तरह एनआईटी के अस्पताल में (यदि इसे 100 बिस्तरों का माना जाये तो) 60 डॉक्टरों की जगह मात्र 27, 100 नर्सों की जगह मात्र 29, प्रयोगशाला के दस कर्मियों की जगह मात्र चार ही लगे हैं। रेडियोग्राफ़रों की 12 पोस्टों की जगह मात्र 3 ही स्वीकृत पोस्ट हैं जिनमें से भी लगा हुआ एक ही है और दूसरा ठेके पर है जो बेहतर नौकरी मिलते ही उड़न-छू हो जायेगा। कुल मिला कर कोई भी मानक पूरा नहीं है। हर तरह के कर्मचारियों का भारी टोटा है, और तो और 37 सफ़ाईकर्मियों की जगह मात्र 20 से ही काम चलाया जा रहा है। सर्वविदित है कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इसके बावजूद राज्य के मज़दूर अपने हाड़-पसीने की कमाई से ईएसआई निगम के माध्यम से राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को कुल खर्च का आठवां भाग देना ही भारी पड़ रहा है, लानत है ऐसी सरकार को। इससे भी दुखदायी बात तो यह है कि सरकार ईएसआई को अपने शिकंजे से मुक्त करने को भी तैयार नहीं है। यदि सरकार हाथ खड़े कर दे तो ईएसआई निगम उस सारी व्यवस्था को स्वयं चलाने को भी तैयार है।

> **सर्वविदित है कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इसके बावजूद राज्य के मज़दूर अपने हाड़-पसीने की कमाई से ईएसआई निगम के माध्यम से राज्य सरकार को पैसा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को कुल खर्च का आठवां भाग देना ही भारी पड़ रहा है, लानत है ऐसी सरकार को। इससे भी दुखदायी बात तो यह है कि सरकार ईएसआई को अपने शिकंजे से मुक्त करने को भी तैयार नहीं है। यदि सरकार हाथ खड़े कर दे तो जो निगम सात हिस्से खर्च कर रहा है, वह आठ हिस्से भी खर्च कर सकता है।**

रेशनलाइजेशन भी चाहती है ईएसआई

मानकों के अलावा, ईएसआई निगम चाहती है कि संसाधनों का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दुरुपयोग न किया जाये। इस तरह के दुरुपयोग के अच्छे-खासे उदाहरण इस राज्य में मौजूद हैं।

भिवानी में जहां मात्र 4000 बीमाकृत हैं, वहां 50 बिस्तरों का अस्पताल पिछले दस बरसों से चल रहा है और गुड़गांव में जहां 3,50000 बीमाकृत बसते हैं, वहां पिछले दस बरसों से अस्पताल अभी बन ही रहा है। वैसे गत एक वर्ष से इमारत तो बन कर खड़ी है, परंतु अस्पताल चालू करने के लिये आवश्यक साज़ो-सामान के लिये इस दौरान चार बार तो टेंडर हो चुके हैं।

अभी कितने वर्ष तक यह सिलसिला चलेगा, राम जाने? इसी तरह, फ़रीदाबाद के सेक्टर-8 वाले अस्पताल की इमारत तो 200 बिस्तरों की है, जिसके चौथाई भाग का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। खाली पड़ी इमारत की जो दुर्दशा हो रही है, उसे देख कर साधारण श्रमिक अपना सिर धुनने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा।

ईएसआई निगम द्वारा 1.4.09 को जारी परिपत्र में मानकों को लागू करने के साथ-साथ निगम की यह भी शर्त है कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके, न कि राजनेताओं के राजनीतिक हित साधने को इनका दुरुपयोग किया जाये। पिंजौर में जहां मात्र 300 बीमाकृत हैं वहां 4 डॉक्टर लगे हैं जो विशेष हितों को साधना चाहते हैं जैसे आईएस परीक्षा आदि की तैयारी। दो डॉक्टर यहां से आईएस बन भी चुके हैं।

ईएसआई का कायाकल्प श्रममंत्री के हाथ में

फ़रीदाबाद (म.मो.) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों एवं औषधालयों को मज़दूरों की भाषा में सीधा ईएसआई कहा जाता है। अकेले इसी शहर में 1,60000 मज़दूर परिवार इस योजना से जुड़े हैं। भारी मात्रा में पैसा देने के बावजूद इन अस्पतालों व औषधालयों में मज़दूरों की जो दुर्दशा होती है, वह देखने लायक है। इसी दुर्दशा से बचने के लिए यथासंभव मज़दूर अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टरों अथवा नीम हकीमों से कराना ही बेहतर समझते हैं। इसी बदइंतज़ामी के चलते मज़दूर, खासकर ऊंचे वेतन पाने वाले मज़दूर इस योजना में शामिल होने से बचना चाहते हैं।

यह योजना बेशक केंद्र सरकार की है, लेकिन स्वास्थ्य सेवायें क्योंकि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए इसे लागू करने का पूरा दायित्व हरियाणा सरकार का है। नियमानुसार अस्पतालों व औषधालयों की ज़मीन खरीदने से ले कर इमारतें बनाने व उसमें सारे साज़ो सामान लगाने का दायित्व ईएसआई निगम का होता है, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले प्रत्येक आठ रुपये में से सात रुपये ईएसआई निगम तथा शेष एक रुपया राज्य सरकार को खर्च करना होता है। लेकिन इस एक रुपया खर्च के बदले इन स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। राज्य सरकार इन सेवाओं में पूरी दादागिरी चलाती है और सेवाओं का दुरुपयोग करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को खुल कर बढ़ावा देती है। दुरुपयोग से बचाने के नाम पर हरियाणा सरकार ने ईएसआई को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से अलग कर के श्रम विभाग से जोड़ दिया, लेकिन दुरुपयोग ज्यों का त्यों जारी है। ऐसा नहीं है कि आठ में से सात रुपये खर्च करने वाली ईएसआई निगम पूरे आठ रुपये खर्च करके स्वयं पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ले तो सकती है, परंतु राज्य सरकार लेने नहीं देती, क्योंकि मात्र आठवां हिस्सा दे कर पूरी सेवाओं पर चौधर एवं दादागिरी को भला राज्य सरकार कैसे छोड़ सकती है? करीब तीन वर्ष पहले तक इन सेवाओं को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने स्वास्थ्य सचिव एवं एक डाइरेक्टर ईएसआई जो राज्य सरकार का ही एक वरिष्ठ डॉक्टर होता है, के माध्यम से चलाते रहे हैं।

लेकिन आजकल श्रममंत्री अपने श्रम सचिव तथा डाइरेक्टर ईएसआई द्वारा इसे संचालित करते हैं। यदि श्रममंत्री के पास ये दो अधिकारी ढंग के हों यानी बेईमान, नालायक, निकम्मे व खुदगर्ज़ न हों तो ईएसआई की काया एकदम देखते ही देखते पलट सकती है, जिस पर सरकार का कोई अतिरिक्त पैसा खर्च होने वाला नहीं। इस सुधार का सीधा लाभ राज्य के साढ़े छः लाख बीमाकृत परिवारों या यों कह सकते हैं कि राज्य की कुल आबादी के साढ़े बारह प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। और यदि सरकार थोड़ी सी जागरूक हो जाये तो यह संख्या दोगुणी हो सकती है।

पूर्व श्रममंत्री ने इन बातों को समझने की बजाये श्रमिकों को बहकाने व अपनी जेबें भरने वाला रास्ता अपनाया था। उनकी समझ थी कि ईएसआई के दरवाजे पर उनकी तस्वीर लग जाने तथा मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का नाटक करने से न केवल श्रमिक बल्कि इलाके की दूसरी जनता भी उनके बहकावे में आ जायेगी। उनको बहुत समझाने का प्रयास किया गया था कि उनका ईएसआई डाइरेक्टर सहारण जो अब सेवानिवृत हो चुका है, अव्वल दर्जे का चापलूस, निकम्मा एवं महाभ्रष्ट है तथा श्रम सचिव राजकुमार, जो अब वहां से बदल चुके हैं, की कामकाज में कतई कोई रुचि नहीं है। लेकिन इन सबके ऊपर चापलूसी एवं 'सेवा पानी' भारी पड़ी और दो वर्षों तक ईएसआई का सत्यानाश होने दिया गया।

मौजूदा ईएसआई डाइरेक्टर सरणा पर भ्रष्टाचार का ठप्पा तो फ़िलहाल नज़र नहीं आया, लेकिन काम काज करने में ढीले ही हैं, हां यदि कोई उनसे रोज़ाना काम काज का हिसाब लेने वाला हो तो उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है।

> **पूर्व श्रममंत्री ने इन बातों को समझने की बजाये श्रमिकों को बहकाने व अपनी जेबें भरने वाला रास्ता अपनाया था। उनकी समझ थी कि ईएसआई के दरवाजे पर उनकी तस्वीर लग जाने तथा मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का नाटक करने से न केवल श्रमिक बल्कि इलाके की दूसरी जनता भी उनके बहकावे में आ जायेगी। उनको बहुत समझाने का प्रयास किया गया था कि उनका ईएसआई डाइरेक्टर सहारण जो अब सेवानिवृत हो चुका है, अव्वल दर्जे का चापलूस, निकम्मा एवं महाभ्रष्ट है तथा श्रम सचिव राजकुमार, जो अब वहां से बदल चुके हैं, की कामकाज में कतई कोई रुचि नहीं है। लेकिन इन सबके ऊपर चापलूसी एवं 'सेवा पानी' भारी पड़ी और दो वर्षों तक ईएसआई का सत्यानाश होने दिया गया। मौजूदा ईएसआई डाइरेक्टर सरणा पर भ्रष्टाचार का ठप्पा तो फ़िलहाल नज़र नहीं आया, लेकिन काम काज करने में ढीले ही हैं, हां यदि कोई उनसे रोज़ाना काम काज का हिसाब लेने वाला हो तो उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है।**

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06